

किया है कि वह अपनी मोहतरिमा को साथ लेकर जा रहे थे और उनको रास्ते में रुकना पड़ा। मुझे उन से हमदर्दी है। लेकिन साथ ही उनको कम से कम इस बात की दाद देनी चाहिए कि रेलवे के महकेने उनको मौका दिया कि वह अपनी मोहतरिमा के साथ एक घंटा तो गुजारें। ज्यादा बक्त तो वह पर्लियामेंट में गजारते हैं, या यारों-दोस्तों से मिलते-जुलते हैं। अगर उनको पहली दफा ऐसा भौका मिले, तो उनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, न कि हमसे नाराज होना चाहिए।

मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें और कोई बात रह गई है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें खचं का तख्मीना वर्गीकृत क्या है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जुलाई, 1973 तक यह पुल ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा।

[अर्थात् निम्नलिखित वाक्य का अनुवान है]—
यानि १५ अगस्त शुरू होनी चाहिए तब तक कि वे यात्रुओं ने अपने बड़े सामान के साथ रेलवे के बन्द होने से शाहदरा और सहारनपुर के बीच का, जो सौ मील लम्बा इलाका उजड़ गया है, उस पर विवार करने के लिए आज आविर में समय मिला है और वह समय भी बहुत कम है। बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे।

18.09 hrs.

DISCUSSION ON RE-OPENING OF S. S. LIGHT RAILWAY FROM SHAHDARA TO SAHARANPUR

श्री रामचन्द्र विकल (वामपाति) : मध्यापति महोदय, शाहदरा-नहारनपुर लाइट रेलवे के बन्द होने से शाहदरा और सहारनपुर के बीच का, जो सौ मील लम्बा इलाका उजड़ गया है, उस पर विवार करने के लिए आज आविर में समय मिला है और वह समय भी बहुत कम है। बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे।

सभापति महोदय : यह एक बंटे का डिसब्यूशन है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि थोड़े-समर में अपनी-अपनी बात रख दें।

श्री रामचन्द्र विकल : मैं बहुत संक्षेप में कुछ तथ्य और तर्क रखना चाहूँगा कि इस रेलवे लाइन के बन्द होने से सौ मील लम्बे इस इलाके के साथ केसा अन्याय किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा उन तथ्यों और तर्कों से पहले माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान माननीय पर्मा जी द्वारा जो पेटीशन कंसटी की रिपोर्ट 22 मई को इसी सदन में प्रस्तुत की गई उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ और मैं विशेषकर उन से प्रारंभना करूँगा कि उस के पृष्ठ 30 और 36 का वह अवश्य अवलोकन करें। मैं थोड़े में उनका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि 13-8-72 को रेल मंत्री जी को लोक सभा के 40 माननीय सदस्यों द्वारा एक स्वृति-पत्र दिया गया, उसमें भी इस रेलवे लाइन के बन्द होने से इस इलाके की तमाम समरणाओं के ऊपर एक विस्तृत नोट दिया गया है। उसकी तरफ भी मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उसको उन्होंने अवश्य पढ़ लिया होगा या नहीं तो आज के बाद उसको अवश्य पढ़ने का काट करेंगे। मैं उनर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के उन पत्रों की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो उन्होंने कई बार इस बात के लिए लिखे कि हमारा बहुत बड़ा से ले इस रेलवे लाइन के बन्द हो जाने से उजड़ रहा है और उनर प्रदेश की सरकार इस रेलवे लाइन के नफा नुकसान में

स्थानीय बदलाव की वजह से उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है।

माननीय सदस्य ने यही कहा कि यह बदलाव की वजह से उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। यही कहा कि यह बदलाव की वजह से उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है।

माननीय सदस्य ने यही कहा कि यह बदलाव की वजह से उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है।

माननीय सदस्य ने यही कहा कि यह बदलाव की वजह से उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है।

[श्री रामचंद्र विकल]

णरीक होने के लिए तैयार है। यह उन्होंने कई बार जशनी भी उनको बताया है और लिखित भी दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस रेलवे लाइन के नफा नुकसान में शरीक होने के लिए तैयार है, मगर इसे चालू किया जाए।

इन तीन वातों की तरफ ध्यान दिलाते हुए मैं रेल मंत्री महोदय के सामने कुछ उन तथ्यों को रखना चाहता हूँ जो इस रेलवे लाइन के बन्द होने के संबंध में अब तक सरकार की तरफ से कहे गये हैं। यह कहा गया कि यह रेलवे लाइन घाटे में थी इसलिए बन्द कर देनी पड़ी। मैं संक्षेप में बतलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी 75 रेलवे लाइनें आज तक घाटे में चल रही हैं जिनमें से पांच-छः के नाम में उद्भूत कर रहंगा। बाकी के चाहेंगे तो सूची प्रस्तुत कर दूँगा। वह रेलने लाइनें हैं—बरहन—एटा, उज्जैन—अगर, बटाला—कादियान, दार्जिलिंग—हिमालय बंगलौर सिटी—बांगरेट, तलाला—बेलवाड़ा, पछोरा—जामनेर। ये वे रेलवे लाइनें हैं जिन्हें भारत सरकार चला रही है मगर घाटे में हैं। इनको क्यों नहीं बन्द किया गया जबकि हमारे इलाके की इस रेलवे लाइन को बन्द किया गया? मैं उन रेलवे लाइनों के नाम भी प्रस्तुत करूँगा जो कम्पनी द्वारा चलाई जाती रही हैं और घाटे में भी चल रही हैं आज भी मगर भारत सरकार उन को सहायता करती आ रही है। ऐसी आज भी जो चालू कम्पनी की रेल है जिनका प्रबन्ध भारत सरकार के हाथ में है और जो घाटे की है, जिनमें सरकार सहायता कर रही है उनके नाम मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ—चपरमुख—सिलघट (आसाम), काटाखाल—लाल बाजार (आसाम), अहमदपुर—कट्टा (बंगाल), बांकुड़ा—दामोदर (बंगाल), फूलगांव—आरवी (महाराष्ट्र), एलिचपुर—योतमाल (महाराष्ट्र)। ये वे रेलवे लाइनें हैं जिनका प्रबन्ध सरकार के हाथ में है मगर कम्पनी की है और घाटे में चल रही हैं। मगर सरकार ने इनको बन्द नहीं किया जब कि हमारे इलाके की रेलवे लाइन को घाटे की बात बता कर

बन्द कर दिया। मैं और भी उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसी रेलवे लाइनें जिनका स्वामित्व और प्रबन्ध कम्पनी के हाथ में था, घाटे में चलती रहीं और भारत सरकार उनकी सहायता करती रही, अब उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया है—फतुबा-इस्लामपुर (विहार) और बंदवान—कट्टा (बंगाल), ये वे लाइनें हैं जिनमें घाटे के बावजूद सरकार सहायता करती रही है, इनका स्वामित्व और प्रबन्ध कम्पनियों के हाथ में था और अब कुछ दिनों से इनका राष्ट्रीयकरण कर लिया है। लेकिन हमारी रेलवे लाइन जो घाटे की नहीं थी न उसको चलाने के लिए कम्पनी को बाध्य किया गया और न कई प्राइवेट कम्पनियों ने जब लिख कर दिया कि उनको चलाने दिया जाय तो उनको भी नहीं चलाने दिया गया। इस पर तो कभी सोचा भी नहीं गया।

अभी हाल में राज्य सभा में गत सप्ताह मार्टिन बन्द कम्पनी की दो बन्द रेलों को पुनः चालू करने का आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया है जिनके नाम हैं हावड़ा-आमता और हावड़ा-शाखला। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि इन घाटे की रेलवे लाइनों को भी चलाने का आश्वासन राज्य सभा में दिया जा चुका तो इसी एस-एस लाइट रेलवे लाइन के लोगों ने क्या ऐसा पाप किया है कि उनकी तरफ अभी तक रेल मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया। समाचार पत्रों से उद्धरण मैं पेश करना चाहता हूँ। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 1967-68 में बराबर लाभ होता रहा। 1967-68 में भी इस रेलवे लाइन में 0.31 लाख रुपये का लाभ हुआ था, लेकिन घाटा बता कर इस रेलवे लाइन को बन्द कर दिया गया। 1969-70 में घाटा हुआ या दो-तीन पिछले सालों में घाटा हुआ, मैं जानना चाहता हूँ उस घाटे के कारणों की जांच क्यों नहीं हुई। इस घाटे का कारण भी मैं समझ रहा तो आप को बताने की कोशिश करूँगा। वह घाटा नहीं होना चाहिये था, उसको रोका जा सकता था इतना बड़ा घाटा नहीं था।

एक बात मैं आप के द्वारा रेलवे मंत्री जी से कहना चाहता हूँ—मार्टिन बन्द कम्पनी इस

रेलवे को बन्द करने से पहले कई बार भारत सरकार से आग्रह कर चुकी थी कि हमको मामूली किराया बढ़ाने दिया जाय और कोयला जिस रेट पर अन्य रेलवे लाइनों को दिया जाता है, उस रेट पर हम को भी दिया जाय, यदि हमें इतनी सुविधा दे दी जाय तो हम इस रेलवे लाइन को छला लेंगे, लेकिन उनकी इस मामूली सी शर्त को भी स्वीकार नहीं किया गया। सरकार ने अपनी रेलों में किराये बढ़ाये हैं, यदि उन नों भी यह सुविधा मिल जाती और कोयला में छूट मिल जाती तो यह रेलवे चलती रहती, लेकिन सरकार ने इतनी उदारता भी नहीं दिखाई।

घाटा भी जो हुआ था, वह स्टाफ का बेतन बढ़ने की बजह से हुआ था। 1967-68 में स्टाफ के बेतन पर 26.64 लाख रुपया खर्च था, लेकिन 1969-70 में यह 29.3 लाख रुपया हो गया, लेकिन यह जो घोड़ा सा घाटा स्टाफ का बेतन बढ़ने से हुआ था कोयले की कमी की बजह से हुआ, यह इतना बड़ा घाटा नहीं था जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी। आज सरकार इस लाइन के 800 सरकारी कर्मचारियों पर 3 लाख रुपया खर्च करती भी, जो घाटे के रूप में इन कर्मचारियों को देती है, अगर यह लाइन चलाई जाती तो घाटा तीन लाख भी नहीं होता। तीन-चार आउट-एजेन्सियाँ सरकार के द्वारा अभी भी इस रेलवे के बड़े स्टेशनों पर चलती हैं, वह भी सरकार के लिये घाटा है। घाटे-नके का हिसाब में नहीं जानता लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि होश्यारी के साथ इस पर सोचा नहीं गया।

इस रेलवे लाइन के बन्द करने से पहले दो प्राइवेट कम्पनियों ने सरकार को लिखा। मैं यह भी बतला दूँ कि जब यह रेलवे लाइन बन्द कर दी गई तो हम प्रधान मंत्री जी से मिले, उस इलाके के लोग उनसे मिले और उस समय स्वयं प्रधान मंत्री जी ने कहा था—अगर कोई कम्पनी, मार्टिन-बन्न के अलावा इस रेलवे लाइन को चलाना चाहती है तो ले आइये। हमने बहुत कोशिश की—एक कम्पनी ने जिस का नाम “रानी मिल” है, उन्होंने अपनी शर्तें लिखकर

प्रधान मंत्री जी को, रेलवे मंत्री जी को और मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को भेजी, लेकिन उनको बुला कर उनसे बात भी नहीं की गई कि वे किन शर्तों पर चलाने के लिये तैयार हैं। अंत में जिन को उद्घाइने के लिये मार्टिन-बन्न कम्पनी में ठेका दिया—लाठ विश्वस्तर दयाल—उन्होंने कहा कि मैं भी चलाने के लिये तैयार हूँ, लेकिन उनको भी सरकार ने नहीं पूछा कि आप की कौन सी शर्तें हैं, या कौन सी जायज शर्तें हैं कौन सी नाजायज शर्तें हैं, उनसे बात ही नहीं की गई। इस कम्पनी ने इस रेलवे लाइन को चलाने के लिये 60 लाख रुपये का मूल्य मांगा था। इस सम्बन्ध में स्टेट बैंक के कर्मचारी मुझे मिले थे, उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार इस लोन की जमानत दे दे तो रेल चलाने के लिये वे किसी भी प्राइवेट कम्पनी को १ प्रथा देने के लिये तैयार हैं। स्टेट बैंक आफ इण्डिया पालियामेंट स्ट्रीट में है, उनके बड़े मैनेजर ने कहा कि कर्ज की बजह से रेल को नहीं रुकने देंगे, लेकिन कोई गवर्नमेंट उम्मी जमानत दे, हम किसी भी कम्पनी को कर्जा देने के लिये तैयार हैं। इस लिये मैं आप से कहना चाहता हूँ कि इस रेलवे के साथ और इस इलाके के लोगों के साथ आज तक न्याय नहीं किया गया।

अन्त में मैं जानता चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि मेरे प्रदनों के स्पष्ट उत्तर मंत्री महोदय दें—भारत सरकार की जो नीति अन्य हानि वाली रेलों के साथ है, वही नीति हमारी इस रेलवे के साथ आज तक क्यों नहीं बरती गई? दूसरे—जिस प्रकार गारन्टी और रिंबेट मिस्टम में भारत सरकार अन्य ६ कम्पनियों वीक्षितपूर्ति में शरीक होती है, इसके साथ भी ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया गया? भारत सरकार इस बात की पूरी-पूरी जांच क्यों नहीं करानी कि एस० एस० लाइट रेलवे जो कुछ वर्ष पूर्व लाभ में थी, अब क्यों घाटे में है, कलकने की मार्टिन बन्न कम्पनी के दफनर का किनारा खर्च एम० एस० लाइट रेलवे पर पड़ता रहा है, जिसके कारण उम्मी घाटे में जाना पड़ा?

मार्टिन बन्न कम्पनी के साथ जो समझौता

[श्री रामचन्द्र विकल]

भारत सरकार ने किया था। उसकी धारा 14 में भारत सरकार को यह अधिकार है कि ठेके को निश्चित समय से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, भारत सरकार जब चाहे समाप्त कर सकती है। 1969 में जब सात साल के लिये ठेके की अवधि बढ़ाई गई तो 1976 तक वह चल सकता था, लेकिन कम्पनी ने सितम्बर, 1970 में इस रेलवे को बन्द कर दिया, उस समय 1976 तक चलाने के लिये सरकार ने कम्पनी को बाध्य कर्यों नहीं किया, उस वक्त इन शर्तों पर ध्यान कर्यों नहीं गया—इन बातों से मुझे संदेह होता है कि रेलवे बोर्ड और कम्पनी ने मिलकर मनमाने तौर पर इस रेलवे को बन्द होने दिया और वैधानिक हासिलोन नहीं अपनाया गया। कम्पनी के लिवटीडेशन में जाते समय भी जो शर्तें थीं ठेके की उन पर ध्यान नहीं दिया गया। कम्पनी को बहुत बेपरवाही से लिवटीडेशन में जाने दिया, यह भी भारत सरकार की एक उदासीनता है या फिर लापरवाही मैं कह सकता हूँ। भारत रास्कार ठेके बढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान करती है और उन बातों पर इस रेलवे लाइन के सम्बन्ध में क्यों नहीं ध्यान दिया गया? जब इसका ठेका 70 में 76 के पहले समाप्त किया गया तो और कितनी रेलवे लाइनों के ठेके समाप्त हुए हैं इसका निश्चित जवाब मैं चाहता हूँ।

इस इलाके की कठिनाइयों के सम्बन्ध में भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस सौ मील के इलाके में छोटी और बड़ी बीस मंडियां हैं व्यापार की, तीन शुगर फैक्टरीज हैं, सहारनपुर, शामली और बागपत में और कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जिसपर इन्टर और डिप्री कालेज न हो। वह स्टेशन दिल्ली से सम्बद्ध होने की वजह से सरकारी, अधं-सरकारी कर्मचारी, दूध बाले, सड़ो बाले और किसान गजदूरों द्वारा दिल्ली आने जाने में जितनी परेशानी हुई है उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। गरीबी घटाने के बगाय मेरे द्वेष में रेल बन्द होने से गरीबी बढ़ी है। सरकारी कर्मचारी टैक्सी या बस से नहीं आ सकते जो कि

रेलवे के पास से आते थे। मैंने इस सम्बन्ध में दुख के साथ सभी से कहा है, रेल मन्त्री जी से कहा है कि आप चलकर देख लीजिए कि हर स्टेशन पर इस रेलवे लाइन के बन्द होने से कितने लोग बेकार हुए हैं, उनकी क्या कठिनाइयां हैं और उसके बाद फैसला कीजिए तब भी मैं मान लूँगा लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया न रेल मन्त्री जी ने, न रेल उपमन्त्री जी ने, कि चल कर सौ मील के उजड़ते हुए इलाके का चलकर निरीक्षण कर ले। समय कम है अन्यथा मैं अनेकों तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करता। मैं केवल यही चाहता हूँ इस रेलवे लाइन को चाहे भारत सरकार स्वयं चलाए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से चलाए, चाहे कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर चलाए और चाहे प्राइवेट कम्पनी चलायें क्योंकि यह इलाके की मौत और जिनदगी का सबाल है। राष्ट्रीय हित को देखते हुए हर हालत में इस इलाके में पुनः रेल अवश्य चलाने की कृपा करें।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Sir, this Shahdara-Saharanpur Light Railway, one of Martin Burns, creatures, was closed on the 1st September, 1970. I cannot understand why the Government could not take over the railways. Because the poor, common men have no vested interests' lobby functioning in Delhi, and that is why we see today that Government is so very anxious to take over Balmer Lawrie at double the cost to benefit somebody, and that is very good to them.

The length of this railway line is 172.7 km., and this railway ran on an average 22 daily passenger trains, and it carried on an average 12,000 passengers. This did not include the goods trains. That shows that the business was very brisk and it was fully supported and patronised and it was really essential for the people in that area. They had 1,400 employees. If we calculate that way, that is, taking five dependents for one employee, this railway provided living bread and butter—for 7,000 people in the country. Sir, these employees received very low wages. The total wage of an employee came to as low as even Rs. 100.

There was a survey committee instituted by the Government of India, and it says—

am quoting an extract :—

"... Although the services provided by the light railway companies generally leave much to be desired, some of them are serving a very useful purpose and in their case, at any rate, if they are to suspend operation, the road services will not, it is felt, be able to cater for the entire volume of traffic offered. Accordingly, it is necessary to ensure that these railways continue to operate and strive to improve the services to standards comparable with those of other railway systems including broad gauge and metre gauge."

They have a pious Industrial Policy Resolution which clearly indicates that Railways must be in the public sector. They draft a Bible for themselves and then they would be more identified for its violation than to its adherence; that is the strongest thing.

I know they have no transport economist. The huge railways system involving Rs 4,000 crores, Indian money, the largest public sector enterprise has not got a proper, mature, experienced, academically educated transport economist. That is why you always catch the wrong end of the stick. This is one of the cheapest forms of transport, the railways, water transport cheapest. Road transport comes last. I give the example of Howrah-Anta light and Howrah Sheakhala light railway. For a monthly ticket, the small trader and the small clerk who came to the city for working, they paid Rs 17. When it was stopped, they had to pay Rs 65 for the same journey. As a result he stopped coming to the city and lost his source of income or he came and crowded the slums of Calcutta, to avoid paying the railways fares. Traction by railways could be done at a fraction of the cost of running the road transport. It is unfortunate that even after 25 years they do not have an integrated national transport policy. Am I not throwing pearls before swines? I had been writing to them for the last five years, to various Ministries and the Prime Minister that unless you have an integrated national transport policy, you cannot really take correct decisions. So far they have been unable to do it. The ones that we had near Calcutta which had been closed down were serving the poorer sections in the hinterland and the interior, particularly people from the low income group.

But the trouble is that in the Planning Commission and in the Government, there is a very powerful road transport lobby which caters to the needs of the foreign investment oriented road transport although road transport costs may be 4-5 times. In spite of that it is being forced upon the common working man in the country. Howrah-Anta and Howrah-Sheakhala employed 1600 persons, Arrah Sesaram and Futwal Islampur had 900 employees, Sahdra-Saharanpur, 1400 and in the head office it had 30+ persons. The track length covered by Howrah-Anta was 86 km and that of Howrah-Sheakhala was 31 km; Arrah-Sesaram covered 114 km and Futwal-Islampur, 47 km while Sahdra-Saharanpur covered 172 km².

As for the number of trains, Howrah-Anta and Howrah-Sheakhala ran 84 trains carrying 30,000 passengers; Arrah-Sasaram ran 18 trains carrying 8,000 passengers. Futwal-Islampur ran 14 trains and carried 6,000 passengers while Sahdra-Saharanpur ran 22 trains carrying 12,000 persons.

All that I wanted to say is : have they understood the business ? What do they believe in ? In over capitalisation ? These light railways are very old and the intrinsic value or book value of the assets have become next to nothing. In spite of that they are rendering a great service, a beneficial service to your economy. You are running a great social service and serving people at practically no cost. Suppose you want to replace these light railways by buses, how much money would be required ? About twenty times the money involved in the light railways. You do not care for them because you do not understand transport economics, the value of over-capitalisation or under-capitalisation.

As far as Howrah-Amra and Howrah-Sheakhala are concerned, I regret to say that a particular political party had been playing politics and had been dilly-dallying. For year people suffered. Although the Prime Minister in her election meetings had given an assurance in 1971, it was delayed till such a long time. Now we read about it but we have to see what actually happens.

We are struggling for reopening these two railways since December, 1970, but now they want to reap a political dividend. Therefore, they are talking about reopening it. I want to urge on the Minister through you that

[Shri Jyotirmoy Bosu]

the employees of all these light railways should be brought under the rules and regulations of the Indian standard railways and whatever those employees get, the employees of light railways also should get. I also urge that the light railways should be taken over, improved and brought to a standard and not abolished.

Finally, I urge on the minister to spell out clearly and truthfully here what the Government's decision is with regard to Sahdara-Saharanpur light railways and also other light railways that are doing a great service to the people of this country.

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : सभापति महोदय, यह जो विवाद उठाया गया है यह हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में रहने वाले नागरिकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। मैं इस प्रश्न से इधर काफी दिनों से सम्बद्ध हूँ और माननीय मंत्री जी को पालियामेट के चालीस मेम्बरों ने 13 अगस्त को लिख कर दिया कि इस रेलवे को चलाना निहायत जरूरी है क्योंकि यह बड़ी मंडियों के बीच से गुजरती है। यहां पर तीन शुगर फैक्ट्रीज हैं और अनाज की बड़ी मंडियां हैं। अगर यह रेलवे लाइन यहां से हटाई गई तो इससे वहां के लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा।

जो सबसे बड़ी बात कही जाती है वह यह कही जाती है कि यह रेलवे इसलिए नहीं चलाई जा सकती कि यह घाटे में चलती थी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप पश्चिम केन्द्र में जो रेलवे चला रहे हैं उस का मैनेजमेंट इतने दिनों से आपके पास है, क्या वह मुनाफा दे रही है? आज पश्चिमी जिलों के लोगों के बिश्वद एक बड़ी साजिश की गई। वह साजिश यह थी कि कि मार्टिन वन कम्पनी ने । करोड़ 37 लाख रुपये में यह लाइन लाला विश्वामित्र लाल के हाथ बेच दिया। आप जानते हैं कि आज रेलवे लाइनें भृत मंगे भाव पर बिक रही हैं। लाला जी ने यह समझा कि यह रेलवे लाइन पूरी उखाड़ कर बेचने से उनको इतना कायदा हो जायेगा कि उनको इस रेलवे लाइन को चलाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।

लेकिन वहां पर एजिटेशन हुआ। एक या डेढ़ मील लाइन उखाड़ने के बाद सारी जनता ने खड़े होकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और लाला जी स्वयं कहने लगे कि मैं रेलवे चलाने के लिए तैयार हूँ।

अब घाटे की बात कही जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कभी मवी महोदय ने इस बात की जांच कराई है कि 35 से 40 परसेंट तक रेलवे का जो मुनाफा होता था वह मार्टिन वन कम्पनी के हेड ऑफिस को चला जाता था जो कलकत्ता में था। आज स्थिति यह है कि जब इतनी बड़ी धनराशि कलकत्ता को चली जाय और उसके बाद इस रेलवे लाइन की कंडीशन न सुधारी जाय, वहां जो इन्तजाम है उसको न ठीक किया जाये फिर भी दूसरी रेलों से मुकाबला किया जाये तो कैसे काम चलेगा? वही पुराने एंजिन हैं, वही सारा पुराना इन्तजाम है, कोयले का भाव बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में यह रेलवे लाइन मुनाफे में कैसे चल सकती है? लेकिन अभी जब मजदूरों का मामला उठा था इस रेलवे के सम्बन्ध में तब कोटि ने कहा था कि रेलवे लाइन नफे में चलती। अदालत का फैसला है कि यह घाटे में नहीं चलती है, लेकिन आज मंत्री महोदय पता नहीं कैसे कहते हैं कि वह घाटे पर चलती है और अदालत की इस बात पर विचार नहीं करते। अगर कम्पनी के टाइम में यह ठीक चल सकती थी तो आज क्यों नहीं चल सकती। और अगर आप समझते हैं कि यह घाटे में चल रही है तो क्यों नहीं आप इस रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करते? इस तरह से यह 90 मील का पैसेज 60 मील का हो जायेगा और यह मुनाफे पर चल सकती है। इस प्राव्यंत्र को हल करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिये। मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस वात्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे?

यू पी गवर्नरमेंट ने भी कहा है कि इसको चलाया जाना चाहिए। जब सभी यह कहते हैं कि इसको चलाया जाना चाहिये तो आप देखें कि किस तरह से इसको चलाया जाए। माननीय सदस्य विकल जी ने कहा है कि चाहे इसको कोआप्रेटिव के आधार पर चलायें, उत्तर प्रदेश

सरकार से बात करके उससे चलवाएं या किसी भी तरह से हो कोई न कोई सिस्टम "इवाल्व" करके इस रेलवे लाइन को आप चलाएं, फिर चाहे आप स्वयं इस रेलवे लाइन को लेकर और इसको बड़ी लाइन में परिवर्तित करके चलाएं ऐसा करके ही लोगों के जो कप्त और तकलीफे हैं, उनको दूर किया जा सकता है। आप की यह नीति भी है कि ट्रांस्पोर्ट की फैमिलिटी, गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिये तो समझ में नहीं आता है कि इस रेलवे लाइन को क्यों उत्थाड़ा जा रहा है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि मंत्री महोदय जन भावनाओं का आदर करते हुए, वहाँ के नुमाइन्दों की माँग को ध्यान में रखते हुए और उत्तर प्रदेश के रहने वालों की जो भावनायें हैं, उनको समझते हुए कोई ऐसा कदम उठायेंगे जिससे यह रेलवे लाइन पुनः चल सके। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके बारे में कोई आश्वासन जरूर दें।

समाप्ति भावोवय : मैं एक निवेदन करता चाहता हूं। हाउस सात बजे तक बंधता है और मिनिस्टर साहब का जवाब भी आप सुनता चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब को सवाल करने का भी इस पर मौका मिल जाए। मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग एक दो सवाल पूछ लें और बाद में उनका जवाब आ जाए और हम सात बजे या उसके दो चार मिनट इधर-उधर इसको खत्म भी कर दें। इससे आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा और हम समय पर इस बहस को समाप्त भी कर लेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जो बहस विकल जी ने शुरू की है उसका मैं स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं उनको बधाइ देता हूं। दो साल से बराबर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रेलवे लाइन को सरकार ले ले और स्वयं इसको वह चलाएं। यह कहा जाता है कि इसको ब्राड गेज बनाकर तब उसको चलाया जायेगा। ब्राड गेज बनाने के लिए अगर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तो यही होगा कि न नी मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। जब आपने कहा

है कि हावड़ा-आमदा रेलवे लाइन को लेने की आप कोशिश कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि इस रेलवे लाइन को भी आप न लें। अगर सवाल यह है कि यह रेलवे लाइन घाटे में चल रही है तो लोग इसके लिए तैयार हैं कि किराया बढ़ा दिया जाए ताकि नुकसान न हो और कुछ आमदानी हो जाए। लाखों लोगों की सहलियत को देखते हुए नुकसान की बात को देखते हुए अगर इस रेलवे लाइन को नहीं चलाया जाता है तो मैं कहांगा कि सरकार भी तो नुकसान में चल रही है और इसका क्या यह मतलब है कि सरकार को बन्द कर दिया जाए? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 17 जुलाई को हमें आश्वासन दिया था कि हम इसको बचाने के लिए तैयार हैं अगर सेटर हमारी मदद करे। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इसमें आप सहारा दें, आप उसकी इस काम में मदद करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद इसको चलायें।

श्री मुल्की राज सेन्नी (देहरादून) : मैं तीन चार सवाल ही पूछता चाहता हूं। घाटे की बात कही गई है। मैं जानता चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि जब इसको कम्पनी चला रही थी तो वह घरने कर्मचारियों को पूरे तरीके से बैनस और भत्ता नहीं देती थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा आनंदोलन हुए थे और हड्डालों हुई थीं? क्या उसकी वजह से कर्मचारियों में अमन्त्रोप व्याप्त नहीं हो गया था और कर्मचारियों ने पूरी छूटी देना बन्द नहीं कर दिया था? उसी कारण से वहाँ टिकिटर्स ट्रेवल क्या वहाँ नहीं चल रहा था और उसके कारण घाटा हुआ।

वहाँ पर बूढ़ों, बीमारों, औरतों और बच्चों को किस तरह तकलीफ हो रही है, इसको भी आप देखें। त्यौहारों और मेलों के अवसर पर तथा गमियों के मौसम में यात्रियों को वहाँ चार-चार और छ-छ; घट्टे खड़ा रहना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय वहाँ स्वयं सफर करके देख ले।

क्या सरकार ने इसकी कोई जांच कराई है

[श्री मुल्कीराम सैनी]

कि इस रेलवे को आवश्यकता है या नहीं ? हम लोगों ने बार-बार कहा है कि घाटे का एक कारण हैं अफिस पर आमदनी का 45 परसेंट खर्च किया जाना है। इनके अतिरिक्त जब कि रेलवेज को कोयला 28 रुपये पर टन की दर से मिलता है, इस रेलवे को वह 72 रुपये पर टन के हिसाब से मिलता था। कोयले की कीमत में यह डिफरेंस और टिकटैम ट्रेवलिंग भी इस घाटे का कारण रहे हैं। क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच कराने की कोशिश की है ? क्या मंत्री महोदय ने इसके लिए कोई समिति बनाई है, या क्या उनका ऐसा करने का इरादा है ? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि श्री विकल और श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो तथ्य रखे हैं, क्या उनको देखते हुए इस रेलवे को नफे में नहीं चलाया जा सकता है ?

क्या यह मत्त नहीं है कि सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक का इलाका हिन्दुस्तान का एक बहुत डेस्टीली पापुलेटिड-घनी आबादी वाला—एरिया है, जो सब से ज्यादा स्कूल, मंडिया और अन्य संस्थान आदि है ? क्या इन तमाम बातों को देखते हुए यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि यह रेलवे घाटे में नहीं नफे में चलेगी ? अगर वह घाटे में भी चले, तो क्या सरकार का यह फर्ज नहीं है कि जनता की सुविधा के लिए इस रेलवे को फिर से फोरन चालू किया जाये, जब कि सारे हिन्दुस्तान में रेलवेज को घाटा हो रहा है और इस रेलवे का घाटा बाद में नफे में बदल सकते हैं ?

श्री इसहाक सम्प्रभली (अमरोहा) : चेयरमैन साहब, क्या मिनिस्टर माहव को यह फेरोरेंडम नहों मिला है कि इस गाड़ी के बन्द हो जाने से इस रेलवे को इस्तेमाल करने वाले उस एरिया के तकरीबन माहे तीन करोड़ इन्सान सज्ज परेशानी में मुबलिला हो गये हैं और जो लगभग अस्सी लाख इन्सान हर साल इस रेलवे लाइन पर आया-जाया करते थे, वे टूक और लारी वालों के रहभों-करम पर हो गये हैं ? क्या यह सही नहीं

है कि आज औरतों, बच्चों और बीमारों को सख्त दुश्वारी हो रही है ? जैसा कि श्री सैनी ने कहा है, यह हिन्दुस्तान का बहुत ही जरखेज और बहुत ज्यादा गल्ला तथा सध्जी पैदा करने वाला इलाका है और वह इस ट्रांसपोर्ट से मेहरूम हो गया है। क्या सरकार इस रेलवे को छलाने के लिए गौर कर रही है, जैसा कि उसकी तरफ से बार-बार वायदा किया गया है ? क्या सरकार ने इस वारे में कोई आखिरी फैसला कर लिया है ? यू० पी० के चीफ मिनिस्टर ने इस वारे में अपना सह्योग देने का वायदा किया है। उसके बाद इस रेलवे को छलाने में क्या मुश्किल पेणा आ रही है ? क्या सरकार ने यह तथा किया है कि मास्टिन बन कम्पनी जैसे प्राइवेट कैपिटलिस्ट ने इस रेलवे को बन्द करके जो एक तरह से चैलेंज किया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाये ? सरकार की तरफ से पब्लिक सेविटर को बढ़ाने और सोशलिज्म की बात की जाती है। इस हालत में क्या इस सरमायादार कम्पनी के सामने हवियार डाल देना, इस चैलेंज को एक्सेप्ट न करना और लोगों को इस आराम से मेहरूम करना सही होगा ? सरकार जो इस चैलेंज को कुवूल करना चाहिए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इस सिलसिले में क्या कर रही है ।

[श्री सुधान संभुल लालदर्बन] : जैराम साहब, कैसी स्थिति बाहर कर भेज रहा है ?
 नहीं मैले करने का कोई इच्छा नहीं कि देनेवाले से अस रिपोर्ट करनी चाहे।
 इस दृष्टि पर क्वार्टर सेन्टर्स हीन में कोर्टों द्वारा इसका उत्तर नहीं दिया गया है।
 एरिया की दृष्टि से देना चाहिए। अस रिपोर्ट करने की अपील बनायी गयी थी। उसका उत्तर नहीं दिया गया है। एरिया की दृष्टि से देना चाहिए।
 आरोहा की दृष्टि से देना चाहिए। एरिया की दृष्टि से देना चाहिए।
 इस दृष्टि पर क्वार्टर सेन्टर्स हीन में कोर्टों द्वारा इसका उत्तर नहीं दिया गया है।
 एरिया की दृष्टि से देना चाहिए।
 एरिया की दृष्टि से देना चाहिए। एरिया की दृष्टि से देना चाहिए। एरिया की दृष्टि से देना चाहिए। एरिया की दृष्टि से देना चाहिए। एरिया की दृष्टि से देना चाहिए।
 एरिया की दृष्टि से देना चाहिए। एरिया की दृष्टि से देना चाहिए।
 [श्री अमरोहा] : यह एक अद्भुत विवाद है। एरिया की दृष्टि से देना चाहिए।

ओहुच्च बन्द पांडे (खलीलालादा) : सभापति महोदय, मैं भवी महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया है कि अगर केंद्रीय सरकार और रेलवे मन्त्रालय हमें सहयोग दें, तो हम इस लाइन को चलायेंगे ? क्या यह सत्य नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस रेलवे लाइन के बन्द हो जाने से बहुत ही कष्ट में है ? क्या यह सत्य नहीं है कि इस रेलवे लाइन के बन्द हो जाने से इस क्षेत्र की बड़ी-बड़ी मंडियाँ बेकार हो गई हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ, इस नवनिर्माण के युग में जब कि और लाइन खोली जा रही है इस लाइन का बन्द किया जाना कितना अनुचित है और एक प्रश्न यह करना चाहता हूँ कि यह घाटा जो होता है क्या यह सत्य है कि मार्टिन बनं कम्पनी ने जब उनको आभास हो गया कि इस लाइन का राष्ट्रीयकरण हो जायेगा, तो अपने सारे पैसे, सारे मुनाफे को कलकत्ते में खर्च किया ?

ओहुस० एम० बनजी : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक सदस्य हमारे यहाँ भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं बिहार के... (ब्यबधान)...बाद में कोई प्रावलम न पैदा हो जाय इसलिए मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : इस समय इस चर्चा के बीच में नहीं।

ओहुस० सलीश बन्द (बरेली) : सभापति महोदय, जो बातें कही जा चुकी हैं उनको मैं दौहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन माननीय भवी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के बहुत जर्जेर इलाके से, हमारे सूचे के ही नहीं बल्कि सारे देश के बहुत उपजाऊ इलाके से यह सीमील लम्बी लाइन गुजरती थी ऐरेठ मुजफ्फरनगर होकर और राजधानी से कुछ 9 मील पर इसकी शुरुआत थी। मैं जानना चाहता हूँ क्या यह सही है कि मार्टिन बनं कम्पनी की बहुत सी लाइनें बंगल में जो बन्द थीं इसी तरह से, उनको किर-

से चलाने का इरादा किया गया है और अगर उनके बारे में यह फैसला हुआ है तो इस लाइन के बारे में सरकार क्यों उदासीन है ? इसके लिए क्या खास बजह है ? क्या दिक्कत है इसको चलाने में ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या मार्टिन बनं कम्पनी को सिर्फ 5 लाख रुपये साल का घाटा या इस लाइन को चलाने में ? क्या यह फिर भी सही है या गलत है ? अगर सही है तो 5 लाख रुपये साल का घाटा सौ मील लम्बी ऐसी रेलवे लाइन में जो ऐसे इलाके से गुजरती है जहाँ घनी आबादी है, मंडियाँ हैं, फैक्ट्रीज हैं और देश का सबसे उपजाऊ इलाका है, उसमें 5 लाख रुपये के घाटे को सरकार सम्बिद्धाइज नहीं कर सकती है, बदौशत नहीं कर सकती है जो इस लाइन को बन्द करने का फैसला हुआ और सरकार ने यह फैसला किया कि वह इसकी लेकर चलाने के लिए तैयार नहीं है ?

तीसरी बात—क्या यह सही है कि इसके 800 आदमी जिनकी तनखावाह 3 लाख रुपये महीना अर्थात् ३६ लाख रुपये साल बनती है, उनको रेलवे विभाग ने अपने यहाँ ऐवजार्ब किया है क्योंकि एक अनाएम्लायमेंट का प्रावलम पैदा हुआ ? उसके कुल 11 सी आदमी थे। उसमें से 800 को आप ले चुके हैं। तो इन बातों को नजर में रखते हुए क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी कि इस लाइन को उखाड़ कर इसकी पटरियों को बेचा जाय जैसा कि जो नये साहब आए हैं उन्होंने शुरू कर दिया है बल्कि करोड़ों आदमियों, इस इलाके के माठ मतर लाख आदमियों का स्थाल करके जो इसमें फायदा उठाते रहे हैं, वह फायदा उनको मिलता रहे, इसलिए इसको तोड़ा न जाय ? इन प्रश्नों का स्पष्ट जवाब मैं मन्त्री महोदय से चाहता हूँ।

ओहुटी० सोहूल लाल (करोल बाग) : सभापति महोदय, इस लाइन के बन्द होने से दिल्ली के ऊपर जो महांगाई का प्रभाव बढ़ा है वह दिल्ली बासे जानते हैं क्योंकि दिल्ली के अन्दर बास तोर से सब्जी और दूध ये दो चीजें ऐसी थीं जो

[श्री टी० मोहनलाल]

कि इस लाइन से प्रति दिन वरावर आया करती थी। इस लाइन का मुझको थोड़ा सा तजुब्बा है। मैं अक्सर सहारनपुर जाया करता था और जब कभी यहाँ लाइन से नहीं जा पाता था तो इससे रात वो जाना हुआ तो चला जाता था। दिल्ली से गो मील के दायरे के अन्दर चलने वाली इस रेलवे लाइन के बन्द होने से दूध जो पहले एक रुपये बीम पैसे किलो मिलता था, वह आज एक रुपये असमी पैसे किलो और दो रुपये किलो मिलने लगा है। सबजी आलू और दीगर चीजें जो हमें मस्ती मिलती थीं उनके भाव दुगुने ही गए हैं क्योंकि ज्यादातर सबजी इस इलाके से आती थी। ट्रक वाला तो अपनी पूरी ट्रक भर कर तब सबजी लाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो इस लाइन के रुपने पर सबजी बाले अपनी दो-दो गठी मिर पर रख कर बेचने चले आते थे। दूसरे स्टूडेंट्स को इससे बहुत नुकसान हुआ है। आज यह हालत है कि बस न मिली तो लेट हो गए। काफी स्टूडेंट्स जो आस-पास के थे इससे आया करते थे। इस लाइन पर तीन शुगर मिलें थीं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि जो लोग इन मिलों में काम करते थे, वे इसी लाइन से आया-जाया करते थे, अब वे लोग वहाँ पर ही बसने लगे हैं, हालांकि उनके घर लोनी और शाहदरा के पास थे।

जहाँ तक नुकसान वाली बात है, भारत सरकार को उमने काफी रुपया भी दिया है। ऐसी बात नहीं थी कि नुकसान हुआ है। रेलवे के बन्द होने के बाद जब हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिले, दिल्ली के सातों एम० पीज ने कहा कि इस रेलवे के बन्द होने से दिल्ली को बहुत नुकसान हुआ है। जैसा श्री विकल जी अभी बतला रहे थे, उम गमय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आप को आपरेटिव सोमायटी बना कर इसको चला लीजिये। हमने कहा कि यह काम हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैसे का सवाल है। आज जब हम समाजवाद का नारा लगाते हैं, समाजवाद के जमाने से गुजर रहे हैं तो मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि इस रेलवे से उस इलाके की गरीब

जनता का ही सम्बन्ध था, वही इसमें बैठती थी। साधन-मम्पन्न आदमी इसमें बैठने वाले नहीं थे। हजारों आदमी अपने रोजगार के सिलसिले में इस रेलवे से आते थे, सबजी लाते थे—आज उनको नुकसान हो रहा है। उस गरीब जनता के लिए अगर हमको थोड़ा-बहुत घाटा भी भूगतना पड़े तो भूगतना चाहिए था। आज सरकार की रेलों में जब 20 लाख रुपये रोज की ओरी होती है, तो इस रेलवे का घाटा इतना बड़ा घाटा नहीं था, जिसको सम्भाला नहीं जा सकता था।

श्री लक्ष्म प्रताप सिंह (बाराबंकी) : सभापति महोदय, घाटे के आधार पर किसी रेलवे लाइन को चलाने से बन्द कर दिया जाय, यह अंग्रेजी हाईटिकोण नहीं है। भारतीय हाईटिकोण को सामने रखते हुए मैं आप से निवेदन बरना चाहता हूँ कि किसी भी रेलवे लाइन को इस आधार पर बन्द न किया जाय कि उसमें घाटा हो रहा है। बरन् इस बात को देखा जाय कि जो हमारी बंतमान नीति है, जिन क्षेत्रों में पिछड़ापन है, जहाँ की जनता की मांग है कि उनके लिए रेलवे लाइन की व्यवस्था की जाय, रेलवे संवालय का कर्तव्य है कि उस आधार पर रेलवे लाइन की व्यवस्था करे।

डा० गोविन्द बास रिणारिया (जांसी) : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उनको यह जात है कि यह क्षेत्र भारतवर्ष का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है और सबसे जनी आवादी का क्षेत्र है। परं यदि किसी कम्पनी को इसमें नुकसान हुआ है या आप की रावें रिपोर्ट इस क्षेत्र के बारे में ऐसा निर्देश देती है कि इस क्षेत्र में रेल चलाने से घाटा होगा, तो मैं कहता हूँ कि कोई एक्नवायरी कमेटी बैठा दें, इस क्षेत्र में आप को सबसे अधिक लाभ होगा।

आप यह भी जानते हैं कि हमारी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के तमाम लोग, जिनमें हमारे सदस्य थी विकल जी और अन्य लोग भी शामिल हैं, सब इस पक्ष में हैं कि वहाँ पर रेलवे लाइन चलाई जाय, मैं आप से आज आश्वासन चाहता हूँ—आप श्रीनगर के निवासी

हैं, ठण्डे क्षेत्र में रहते आए हैं, हर चीज को ठण्डे तरीके से सोचते हैं—इस मामले पर ठण्डे दिमाग से सोचकर फैसला करेंगे और हमें आज आश्वासन देंगे कि आप शीघ्र इस लाइन को चलाने की कृपा करेंगे। आज हम लोग आपसे आश्वासन लेकर ही उठेंगे—यह निश्चय करके हम सब यहाँ आये हैं।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सभापति जी, कुछ अर्सें से बहुत से माननीय सदस्य चाहे वे हमारी पार्टी से ताल्लुक रखते हों या मुख्यालिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते हों, इस मामले को मेरे सामने लाते रहे हैं और काफी दिलचस्पी जाहिर की है। कभी-कभी यह भी कहा गया है कि अगर यह लाइन न चलाई गई तो इससे लोगों को काफी नुकसान होगा, लोगों को काफी तकलीफ होगी...

श्री ज्योतिमंथ बमु : यह हिन्दी नहीं, उर्दू है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मुझे बोलने वें तो मैं हिन्दी भी बोल सकता हूँ।

श्री इसहाक सम्भली : यह हिन्दी है। लेकिन ये बेचारे तो न हिन्दी जानते हैं और न उर्दू।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सबसे पहले इस रेलवे का थोड़ा सा इतिहास समझ लेना जरूरी है। यह रेलवे 1905 में शुरू की गई थी। उस वक्त से हमारी गवर्नमेंट के साथ 1935 तक इसका कोई ताल्लुक नहीं था। 1935 में जब गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट प्रायुलगेट हुआ तो उसके बाद में मर्कजी सरकार से सम्बन्ध हुआ। इसके बाद कुछ शर्तें थीं कंट्रैक्ट में कि अगर गवर्नमेंट चाहे हर सात साल के बाद इस रेलवे को खरीद सकती है लेकिन कोई जरूरत महसूस नहीं हुई इस कम्पनी को लेने की। इस कम्पनी ने इजहार किया इस बात का कि उन्हें नुकसान हो रहा है और उसकी वजूहात यह बताई कि यू० पी० गवर्नमेंट ने वहाँ पर ट्रक्स के चला दी हैं, बसेज चला दी हैं जिसकी

वजह से काफी ट्रैफिक बसेज और ट्रक्स पर चला गया है। इसके मुतालिक उन्होंने जो आंकड़े दिये उनसे भी साबित होता था कि शायद इस कम्पनी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक 1956-57 में तकरीबन 58 लाख लोग सफर करते थे लेकिन 1969-70 में जिन लोगों ने सफर किया उसकी तादाद कम हो गई, 45 लाख लोग ही सफर करने लगे। इस तरह करीब 20 परसेंट की कमी हुई। इस कमी के बायस उन्होंने कहा कि नुकसान हो रहा है। नुकसान के जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं उसमें उन्होंने बताया कि 1958-59 से 1968-69 तक कुल मिला कर जो सारा नुकसान हुआ वह 16 लाख 27 हजार रुपया था और 1969-70 में 7 लाख 45 हजार का नुकसान हुआ। तो उन्होंने फैसला किया, चूंकि प्राइवेट कम्पनी थी और गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं था, कि 1970 में इस कम्पनी को बन्द कर दिया जाये। बन्द करने से हम यह महसूस करते हैं कि लोगों को काफी तकलीफ हुई, काफी दिक्कतें होती रहीं लेकिन माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि जो रेलवे 1905 में शुरू की गई थी उसके रोलिंग स्टाक की, इंजनों की, कोचेज की और वैगन्स की हालत कितनी खराब और खस्ता हो सकती है। तो इस मसले पर मौके-मौके पर गवर्नमेंट ने दिलचस्पी दिखाई, मार्टिन बर्न से भी तज्जिरा होता रहा कि इसको बन्द न करें लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमें नुकसान हो रहा है और यह नुकसान 1958 से आगे अब तक होता रहा है।

मैं यहाँ पर एक बात बाज़ य करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पालिसी है रेल चलाने की उसमें रुपए का खास ख्याल नहीं रखा जाता है बल्कि लोगों की सुविधा का और आराम का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि अमता हावड़ा रेलवे के लिए आश्वासन दिया गया है कि उसको बन्द नहीं किया जाएगा तो फिर इसके मुतालिक ऐसी बात क्यों नहीं हुई। मैं माननीय सदस्यों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और इस सदन को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि मैं उनके

[شڑی مُہتمم دشکی کو رئیسی]

जजबात और खाड़ाहिंशात को समझते हुए इस बात का ऐलान करता है कि उस्ली तौर पर गवर्नरमेंट ने जान लिया है कि इस रेलवे लाइन को चलाया जाये। अब सवाल है कैसे और कब। मैं समझता हूँ इसके लिए माननीय सदस्य मुझे थोड़ा सा समय देंगे। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यहाँ पर सजेट किया है और यू. पी. की जो सरकार है उसके मुख्य मंत्री ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है और हमारी पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने, मुख्यालिक पार्टियों के जो लोग हैं उन्होंने और जो उस इलाके से तास्लुक रखते हैं उन्होंने काफी दिलचस्पी इसमें ली है तो हम चाहते हैं, ऐसा एक खाल है कि यू. पी. गवर्नरमेंट के साथ एक जबाइंट कार्पोरेशन बनाया जायेगा, यू. पी. गवर्नरमेंट का और रेलवे मिनिस्ट्री का जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से टैक्निकल नालेज और जो एक्सपर्टीज हमारे पास है उसको दिया जाए और उसमें यू. पी. गवर्नरमेंट भी कुछ न कुछ दिलचस्पी लिए रहे। अब जो हमारे मेस्टर वहाँ से आते हैं उस इलाके से कम से कम उन पर इस बात की जिम्मेदारी आती है कि वे देखें कि जब रेलवे चलाई जायेगी तो रेल रोड का जो कम्प्यूटरिशन है उसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि रेलवे की पालिसी हमेशा यही रही है कि हम मुकाबले में नहीं जाना चाहते, जहाँ पर रोड ट्रान्सपोर्ट अवाम के लिए कायदेमन्द हो सकता है वहाँ पर उसको जाना चाहिए और जहाँ रेल वे फायदेमन्द तरीके से काम कर सकती है वहाँ रेलवे की जाना चाहिए। यहाँ पर जो कम्प्यूटरिशन हुआ है उन्हीं रूट्स पर मैं समझता हूँ उसमें कमी की जायेगी, माननीय सदस्यों का सहयोग हमारे साथ रहेगा और मैं यकीन करता हूँ कि बहुत जल्द इस मशिवरे के साथ यू. पी. गवर्नरमेंट से बात करके इस रेलवे लाइन को दोबारा चालू किया जायेगा।

[شڑी मुहर्षी त्रिवियन, वार्षिक दृष्टि, اصلांचली, गोरक्षणी बोर्ड से सभता से बांधदेश]
— ۴۳۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔
— ۴۴۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔
— ۴۵۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔
— ۴۶۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔
— ۴۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔

दौसे त्रिवियन कार्बोन सिंसिटिव्स में स्ट्रेचरेट सिस्टम को लगाऊ था। उस के द्वारा कॉर्टिलियन क्लिप्स की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन कौनी प्रदूषित मॉस नहीं होती थी। अब जैकी ने एलिंग विल्सन की जगह एलिंग विल्सन के इंजीनियरिंग विल्सन को लेकर जाया है। एलिंग विल्सन के इंजीनियरिंग विल्सन ने एलिंग विल्सन के द्वारा लिये गये संस्करण को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन का जैकी को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन का जैकी को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन का जैकी को लेकर जाया है।

मैं यहाँ पर एक बात का ध्यान देता हूँ कि गोरक्षणी को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है।

मैं यहाँ के लिये एक बात की सर्वोच्चता की क्षमता है यहाँ जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है।

मैं यहाँ के लिये एक बात की सर्वोच्चता की क्षमता है यहाँ जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है।

मैं यहाँ के लिये एक बात की सर्वोच्चता की क्षमता है यहाँ जाया है। अब जैकी के लिये एलिंग विल्सन की जैकी को लेकर जाया है।

मैं यहाँ के लिये एक बात की सर्वोच्चता की क्षमता है यहाँ जाया है।

19.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till
Eleven of the Clock on Tuesday,

August 29, 1972/Bhadra 7,

1894 (Saka)